जेबीसी से पहले पांच हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी

एमएसएमई में दो हजार करोड़ का निवेश आगे बढ़ा

जासं, लखनऊ : ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जेबीसी) से पहले राजधानी में पांच हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों की जमीन तैयार है। दो लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में जुटे प्रशासन को उम्मीद है कि सेरेमनी से पहले कई और बड़े निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी मिल जाएगी। अगले कुछ माह में ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, जिसमें निवेश के प्रस्तावों को जमीन पर उतारा जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गत फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। देश और दुनिया भर के निवेशकों ने इन्वेस्टर्स समिट में दिलचस्पी दिखाई जिसका परिणाम रहा कि लखनऊ में ही दो लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए थे। सबसे अधिक निवेश के प्रस्ताव सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) सेक्टर में आए। इसमें करीब साढ़े चार हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए थे। एमएमएमई के अलावा एनर्जी सेक्टर, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, पर्यटन व लाजिस्टिक, शिक्षा और कई दूसरे सेक्टर में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। डीएम सूर्यपाल गंगवार के मुताबिक लखनऊ में निवेशकों ने जो विश्वास जताया है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। करीब सवा सौ प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुके हैं जिनमें तीन हजार करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद है। एमएसएमई सेक्टर जो सबसे अहम है उसमें 47 प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है। इन प्रोजेक्ट से राजधानी में दो हजार करोड़ का निवेश होगा। इसके अलावा सौ के करीब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसकी जमीन को लेकर कुछ मुद्दे हैं जिन पर बात हो रही है। इनमें से अधिकांश प्रोजेक्ट की जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्थानांतरण को लेकर बात चल रही है। जैसे ही इस पर निर्णय होगा वह प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएंगे।

2738 करोड़ के 95 प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पाइप लाइन में ही अटके रह गए

3200 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होने की जताई जा रही उम्मीद

समिट के कुछ निवेश प्रस्ताव

सेक्टर	प्रस्ताव	निवेश
एनर्जी	15	63060 करोड़
हाउसिंग	167	39269 .9 करोड़
शहरी विकास	27	17502 .6 करोड़
यूपीसीडा	35	13999 .9 करोड़
स्वास्थ्य	22	6440 .37
एमएसएमई	201	4557 .95

निवेशकों के साथ हो रही हैं नियमित बैठकें

अपर मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार सिंह के मुताबिक निवेशकों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन हो रहा है ताकि अगर उनको प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरह की दिक्कत हो तो तत्काल उसका समाधान किया जा सके। बैठकों में सभी संबंधित विभाग के अफसर भी रहते हैं जिससे समस्याओं पर वहीं बात हो जाती है। इन बैठकों में औद्योगिक प्रोत्साहन की दिशा में किए जा रहे प्रयास तथा उद्यम स्थापना के विस्तार से संबंधित विभागीय अनापत्ति, स्वीकृति एवं सहमति देने संबंधी जानकारी और समस्याओं के निस्तारण की जानकारी भी दी जा रही है।